नईदुनिया

सऊदी अरब ने कच्चे तेल की पाइपलाइन ईस्ट-वेस्ट को बंद करने का किया ऐलान

रियाद

सऊदी अरब ने अपनी रणनीतिक ईस्ट-वेस्ट कच्चे तेल की पाइपलाइन को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, इस पाइपलाइन को एक दिन पहले रियाद और मदीना क्षेत्रों में कई हमलों का निशाना बनाया गया था। हालांकि, मंत्रालय ने हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं बताई है और न ही पाइपलाइन को हुए नुकसान की जानकारी दी है।

ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के अनुसार, ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। यह देश के तेल क्षेत्रों को लाल सागर स्थित निर्यात टर्मिनलों से जोड़ती है और फारस की खाड़ी से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने के बाद इस पाइपलाइन की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने पिछले महीने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के प्रभाव को कम करने में इस पाइपलाइन ने आपातकालीन तेल भंडार जारी करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सऊदी अरब के लाल सागर स्थित तेल निर्यात मार्ग पर भी दबाव बढ़ रहा है। यमन की ओर से सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों और समुद्री नाकेबंदी की घोषणा के बाद क्षेत्र में तेल परिवहन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि, जुलाई में यमन की सेना ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा करते हुए इसे घेराबंदी के बदले घेराबंदी की रणनीति बताया था।

जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में लाल सागर के रास्ते सऊदी तेल के प्रवाह में भारी गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी शहर यानबू से सऊदी कच्चे तेल और कंडेनसेट की लोडिंग छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई।

वहीं, मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफार्म वोर्टेक्सा ने अगस्त में यानबू से लोडिंग करीब 32 लाख बैरल प्रतिदिन आंकी, जबकि केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक यह लगभग 15 लाख बैरल प्रतिदिन रही।

पाइपलाइन बंद करने का फैसला ऐसे समय में आया है जब सऊदी अरब के कच्चे तेल उत्पादन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के अनुसार, अगस्त में सऊदी अरब का तेल उत्पादन घटकर करीब 62.4 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जबकि जुलाई में यह लगभग 81 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह 1990 के बाद सऊदी तेल उत्पादन का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। यह गिरावट ऐसे समय में हुई है जब सऊदी अरब और ओपेक के अन्य देश तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ रहे थे। क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी के कारण तेल बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जबकि सप्ताह के अंत तक तेल की कीमतों में 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिका ने जमीन के नीचे छिपा रखा है तेल भंडार

वाशिंगटन। आपात स्थिति से निपटने और अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक ऊर्जा झटके से बचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका कच्चे तेल का एक बड़ा आपातकालीन भंडार रखता है, जिसे रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) के रूप में जाना जाता है। जमीन के ऊपर बड़े टैंकों में लाखों बैरल भंडारण करने के बजाय, अमेरिका इस रणनीतिक भंडार के ज्यादातर हिस्से को टेक्सास और लुइसियाना के तटों के साथ बड़ी नमक गुफाओं में जमीन के नीचे रखता है। एसपीआर की उत्पत्ति 1973-74 के अरब तेल प्रतिबंध से हुई, जब तेल उत्पादक देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को निर्यात प्रतिबंधित कर दिया था। इससे गंभीर ऊर्जा कमी और तेल कीमतों में तेजी आई, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी उजागर हुई। जवाब में, अमेरिका ने 1975 में SPR की स्थापना की, ताकि आपातकाल में तेल आपूर्ति बाधित होने पर इसका उपयोग किया जा सके। अमेरिका ने भूमिगत नमक संरचनाओं को कई फायदों के कारण चुना। नमक की गुफाएं दीर्घकालिक कच्चे तेल के भंडारण के लिए आदर्श हैं क्योंकि नमक कच्चे तेल को आसानी से अवशोषित नहीं करता है, जिससे पेट्रोलियम लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जमीन के नीचे होने से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिलती है। सतह के नीचे गहराई में उनका स्थान चरम मौसम, दुर्घटनाओं और संभावित हमलों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है, जो राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण है। लागत एक और बड़ा फायदा है।

ईरान में फूटा महंगाई बम, क्या फिर सड़कों पर उतरेगी भूखी जनता

तेहरान। आठ महीने से जारी युद्ध के कारण ईरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई दर 70 प्रतिशत के आसपास है, जबकि खाने-पीने की चीजों की कीमतें 128 प्रतिशत से भी ऊपर हैं। ईरानी मुद्रा रियाल रिकार्ड निचले स्तर पर है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति न के बराबर रह गई है। औसत मासिक वेतन करीब 125 डालर है, जबकि बुनियादी खर्च 450 डालर तक पहुंच जाता है, जिससे पेट्रोल, भोजन और रोजमर्रा की वस्तुएं आम परिवारों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग रसीदें और पुरानी कीमतों की तुलना करके अपनी परेशानी दिखा रहे हैं। अमेरिका ने आपरेशन इकोनामिक आउटकास्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य ईरान की अर्थव्यवस्था और खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स (आईआरजीसी) के वित्तीय स्रोतों को काटना है, क्योंकि आईआरजीसी देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। रिपोर्टों के मुताबिक, कई आईआरजीसी सदस्यों को महीनों से वेतन नहीं मिला है और वे परिवार के लिए भोजन मांगने को मजबूर हैं।

चीन खुद उगाता है सोयाबीन फिर भी अमेरिका से खरीदा लाखों टन सोयाबीन

बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका जाने वाले हैं, उससे पहले चीन अमेरिकी सोयाबीन खरीद रहा है। पिछले दो महीनों में चीन ने लाखों मीट्रिक टन सोयाबीन अमेरिका से खरीदा है। इसी हफ्ते करीब करीब 10 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन बिजिंग पहुंचा। सवाल ये कि जब चीन खुद भारी मात्रा में सोयाबीन उगाता है तो उसे अमेरिकी सोयाबीन की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सरकारी अनाज खरीदने वाली एजेंसी ने अमेरिका के साथ करीब 14-15 खेप सोयाबीन खरीदने के सौदे किए हैं। इनकी डिलीवरी दिसंबर से फरवरी के बीच गल्फ टर्मिनलों से की जाएगी। इसे लेकर चीन अब तक करीब 1.25 करोड़ टन सोयाबीन खरीद चुका है। चीन ने अमेरिका से वादा किया था कि वह हर साल सिर्फ 2.5 करोड़ टन सोयाबीन खरीदेगा, लेकिन 2-3 महीनों में ही आधे से ज्यादा सोयाबीन चीन खरीद चुका है। माना जा रहा है कि चीन अमेरिका को लुभाने और अपने मन मुताबिक ट्रेड डील के लिए ऐसा कर रहा है।

उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर दागीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें, दक्षिण कोरिया ने बढ़ाई निगरानी

सियोल

उत्तर कोरिया ने ईस्ट सी (पूर्वी सागर) की ओर कई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक, यह लान्च दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच पांच दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज के समाप्त होने के एक दिन बाद हुआ।

दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक दक्षिण कोरिया के जाइंट चीफ्स आफ स्टाफ (जेसीएस) ने बताया कि सुबह करीब 5:20 बजे उत्तर कोरिया के वोनसन इलाके से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का पता चला। मिसाइलें समुद्र में गिरने से पहले करीब 250 किलोमीटर तक उड़ीं।

जेसीएस ने कहा कि दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उत्तर कोरिया की सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। मिसाइल लान्च से जुड़ी जानकारी जापान के साथ भी साझा की गई है।

दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा, हमारी सेना दक्षिण कोरिया-अमेरिका की मजबूत रक्षा स्थिति के तहत उत्तर कोरिया की विभिन्न गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है और किसी भी उकसावे का करारा जवाब देने की क्षमता और तैयारी बनाए हुए है।

दक्षिण कोरियाई सैन्य सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती आकलन में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कोरिया ने कई बार ह्वासोंग-11 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों और 600 मिलीमीटर मल्टीपल राकेट लान्चर से गोले दागे।

जेसीएस ने संभावित अतिरिक्त मिसाइल लान्च को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है और दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा जापान के बीच सूचना साझा करने के साथ सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।

यह मिसाइल परीक्षण दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के संयुक्त फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास के ठीक बाद हुआ। पांच दिवसीय यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू के पूर्व और दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में आयोजित किया गया था।

अभ्यास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हुआ। इससे पहले सियोल और वाशिंगटन ने अपना वार्षिक संयुक्त उल्ची फ्रीडम शील्ड (स्नस) अभ्यास कम स्तर पर आयोजित किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने दक्षिण कोरिया-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों में कटौती का आदेश दिया था। ट्रंप ने इन अभ्यासों को महंगा बताते हुए कहा था कि उत्तर कोरिया के लिए ये गतिविधियां अनुचित और शत्रुतापूर्ण संकेत देती हैं।

मिसाइल लान्च से कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री किम सोंग-गी ने तीन देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी उत्तर कोरिया के साथ नया सैन्य टकराव भड़काने की कोशिश करते हैं, तो प्योंगयांग अपनी ताकत के दम पर कड़े जवाबी कदम उठाएगा।

उत्तर कोरिया लंबे समय से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। प्योंगयांग इन अभ्यासों को संभावित हमले की तैयारी के तौर पर देखता है और अक्सर इनके विरोध में मिसाइल व अन्य हथियारों के परीक्षण करता है।

मिसाइल परिक्षण ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने के अंत में वाशिंगटन में अहम बैठक होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि दोनों नेताओं की बैठक के एजेंडे में उत्तर कोरिया और कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा स्थिति से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।

यमन की सेना का दावा- लाल सागर तट के बड़े इलाके पर कब्जा, सैकड़ों सऊदी समर्थित लड़ाके मारे गए

सना

यमन में सऊदी अरब के खिलाफ सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। यमनी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने दावा किया है कि सेना ने हुदैदाह और ताइज़ प्रांतों में करीब 5,400 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है और सैकड़ों सऊदी समर्थित लड़ाकों को मार गिराया या घायल किया है। प्रवक्ता ने बाब अल-मंदाब की ओर बढ़ने और सऊदी ठिकानों के खिलाफ हमले तेज करने की भी चेतावनी दी है।

ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के मुताबिक टेलीविजन पर दिए बयान में सरी ने कहा कि यमनी सेना और पापुलर कमेटियों से जुड़े लड़ाकों ने दोनों प्रांतों के छह जिलों से सऊदी समर्थित बलों को खदेड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि अभियान के दौरान सऊदी समर्थित लड़ाकों की सात डिवीजनों और 38 ब्रिगेड को पराजित किया गया।

सरी के अनुसार, लड़ाई में सैकड़ों लड़ाके मारे गए या घायल हुए, जबकि कई अन्य को हिरासत में लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सैन्य बलों ने उन कई कैदियों को मुक्त कराया, जिन्हें कथित तौर पर सऊदी समर्थित बलों द्वारा संचालित हिरासत केंद्रों में रखा गया था।

यमनी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने 32 अभियान चलाए और सऊदी विमानों की घुसपैठ को रोकते हुए नौ विमानों को मार गिराया। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि का तत्काल कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

सरी ने कहा कि यमनी सेना लाल सागर में जहाजों की आवाजाही को लेकर अपनी घोषित नीति पर कायम है। उनके मुताबिक, सऊदी अरब से आने वाले जहाजों को छोड़कर अन्य जहाजों के लिए लाल सागर से गुजरने की अनुमति रहेगी।

उन्होंने इसे घेराबंदी के बदले घेराबंदी की नीति बताते हुए कहा कि जब तक यमन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी जारी रहेगी, सऊदी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहेगा।

यमन में संघर्ष वर्ष 2015 में उस समय तेज हुआ, जब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमनी सरकार के समर्थन में सैन्य अभियान शुरू किया। इस संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और देश गंभीर मानवीय संकट से गुजरता रहा है।

यमनी सेना के प्रवक्ता के ताजा दावों के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

पाकिस्तान में बच्चों के आनलाइन यौन शोषण पर यूनिसेफ ने जताई चिंता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में 12 से 17 वर्ष की उम्र के करीब 15 लाख इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चे एक साल के दौरान तकनीक के जरिए होने वाले यौन शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार हुए। इसका मतलब हर 16 में से एक बच्चे ने इस तरह की ज्यादती का सामना किया। यूनिसेफ ने पाकिस्तान में बच्चों के आनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान सरकार, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, न्यायिक एवं सामाजिक सेवा संस्थानों, समुदायों, स्कूलों, परिवारों और डिजिटल प्लेटफार्म से मिलकर बच्चों के लिए आनलाइन तथा वास्तविक जीवन में सुरक्षित वातावरण तैयार करने और रोकथाम, सुरक्षा एवं प्रतिक्रिया व्यवस्था मजबूत करने का यूनिसेफ ने आह्वान किया है। पाकिस्तान में नुकसान रोकना : टेक्नोलाजी से बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मिले प्रमाण नामक रिपोर्ट यूनिसेफ के आफिस आफ स्ट्रैटेजी एंड एविडेंस इनोसेंटी, ईसीपीएटी इंटरनेशनल और इंटरपोल ने संयुक्त रूप से तैयार की है। इसके लिए सेफ आनलाइन से वित्तीय सहयोग मिला। अध्ययन में 12 से 17 वर्ष के बच्चों और उनके माता-पिता तथा देखभाल करने वालों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि घरेलू सर्वेक्षण के साथ फ्रंटलाइन और न्याय क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के साक्षात्कार शामिल किए गए।

यूएन महासभा में जलवायु न्याय और मुआवजे के लिए पांच मुद्दे उठाएंगे पीएम बालेन्द्र शाह

काठमांडू

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की तैयारी में हैं। न्यूयार्क में आगामी 24 सितंबर को महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शाह जलवायु न्याय और क्षतिपूर्ति से जुड़े पांच प्रमुख एजेंडे प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री 22 सितंबर को न्यूयार्क के लिए रवाना होंगे, जबकि उनसे पहले विदेश मंत्री शिशिर खनाल 20 सितंबर को न्यूयार्क पहुंचेंगे।

विदेश सचिव अमृत बहादुर राई के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि जलवायु परिवर्तन और इससे पैदा होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण नेपाल को बार-बार बड़े पैमाने पर जनधन के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल का कार्बन उत्सर्जन बेहद कम होने के बावजूद वह जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभाव झेल रहा है।

प्रधानमंत्री वैश्विक समुदाय से जलवायु न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान करेंगे। नेपाल इस बात पर जोर देगा कि जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए उसे तत्काल और उचित क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए।

नेपाल सरकार पहले ही जलवायु आपदाओं से हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डालर के मुआवजे की मांग कर चुकी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस मांग पर लास एंड डैमेज फंड की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

इसके अलावा नेपाल विकसित और समृद्ध देशों से जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण, क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने और संबंधित पक्षों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीक तथा जलवायु वित्त को आसान और रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराने की अपील करेगा। नेपाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान को भी प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली, 46 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र, विशाल हिमालयी क्षेत्र और व्यापक नदी प्रणाली के जरिए वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में नेपाल की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा।

विदेश सचिव अमृत बहादुर राई ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा नेपाल के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पिछले वर्ष के जेन-जी आंदोलन, उसके बाद हुए सफल चुनाव और बड़े जनादेश के साथ बनी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं को रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही नेपाल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना को जारी रखने तथा उसे और बढ़ाने का आह्वान भी करेगा। महासभा के दौरान नेपाल सगरमाथा से समुद्र तक : जलवायु उत्थानशील भविष्य के लिए आह्वान शीर्षक से एक अलग बैठक भी करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण खासकर हिमालयी क्षेत्रों पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव और उससे पैदा होने वाली विनाशकारी परिस्थितियों पर चर्चा करना तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस गंभीर संकट की ओर आकर्षित करना होगा। इस मंच के जरिए नेपाल यह संदेश देने की तैयारी में है कि जलवायु संकट पैदा करने में उसकी भूमिका बेहद कम होने के बावजूद उसके दुष्परिणामों का बोझ नेपाल जैसे पर्वतीय और विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है।

बाढ़ से 14,455 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, 396 छात्र और 21 शिक्षक अब भी लापता

काठमांडू

नेपाल के विनाशकारी बाढ़ का असर रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जिलों की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। बाढ़ से तीनों जिलों में 14,455 से अधिक बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन तीन जिलों के 63 स्कूल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, बाढ़ के बाद अभी भी 396 विद्यार्थी और 21 शिक्षक लापता हैं, जबकि 20 विद्यार्थियों और दो शिक्षकों के शव बरामद किए जा चुके हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा मौके पर किए गए अध्ययन के आधार पर तैयार शैक्षिक क्षति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित 63 स्कूलों में 50 सामुदायिक, 11 निजी और दो धार्मिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में कुल 14,455 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में अभी तक नियमित रूप से कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी हैं।

बाढ़ ने 12 शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इनमें आठ सामुदायिक, तीन निजी और एक धार्मिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा 11 स्कूलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इनमें छह सामुदायिक, चार निजी और एक धार्मिक विद्यालय हैं। 25 स्कूलों को होल्डिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन केंद्रों में करीब 2,270 विस्थापित लोगों को रखा गया है। इसके कारण इन स्कूलों में भी फिलहाल पढ़ाई शुरू करना संभव नहीं है।

मंत्रालय के अनुसार, 15 स्कूल भवनों को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मानवीय क्षति और अन्य परिस्थितियों के कारण वहां भी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं हो पा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराई ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन से 23 शैक्षणिक संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 25 स्कूलों का इस्तेमाल विस्थापित नागरिकों के आश्रय स्थल के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में तत्काल पढ़ाई शुरू करने की स्थिति नहीं है। विस्थापितों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए स्थानीय निकायों के साथ समन्वय शुरू कर दिया गया है। तीनों जिलों में सबसे ज्यादा शैक्षिक नुकसान नुवाकोट में हुआ है। यहां 11 स्कूल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 16 स्कूलों को होल्डिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य स्कूल में भवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नुवाकोट में कुल 6,315 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसी तरह धादिंग में आठ स्कूल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि दो स्कूलों को होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। चार अन्य स्कूल पढ़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन विद्यार्थियों के स्कूल नहीं पहुंचने के कारण वहां भी कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी हैं। धादिंग में इन सभी प्रभावित स्कूलों में कुल 5,066 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। रसुवा जिले में चार स्कूल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि सात स्कूलों में विस्थापित लोगों को रखा गया है। इसके अलावा 10 अन्य स्कूलों में भी विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, कुल मिलाकर रसुवा में 3,074 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बाढ़ से हुई तबाही के बाद इन तीनों जिलों में शिक्षा व्यवस्था को सामान्य करने के लिए स्कूल भवनों की मरम्मत, विस्थापित परिवारों का पुनर्वास और लापता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की तलाश अब बड़ी चुनौती बनी हुई है।